

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि : 06.02.2024

नि.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.), 20/2018, सि.वि.सं. 35421/2018 और 54800/2022

सुपरन श्वीस्टेकनिक इंडिया लिमिटेड ..... अपीलकर्ता  
द्वारा: श्री संजीव के. सिंह और सुश्री  
अनुप्रिया आलोक, अधिवक्तागण  
बनाम

मोदी हाइटेक इंडिया लिमिटेड ..... प्रत्यर्थीगण  
द्वारा: सुश्री अमिता सहगल और श्री सौरभ  
पांडे, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बाखरु

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

न्या. विभू बाखरु, (मौखिक)

1. अपीलकर्ता ने सि.वा.(वाणि.) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 02.04.2018 (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश') पर आक्षेप करते हुए वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील दायर की है। मोदी हाइटेक इंडिया लिमिटेड आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा दायर वाद को

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा शुरू किए गए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'सि.प्र.सं.') के आदेश XIII क के तहत खारिज कर दिया गया था।

2. अपीलकर्ता ने *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रार्थना करते हुए उक्त वाद दायर किया था कि प्रत्यर्थी को व्यापार चिह्न/लेबल "VAC-PAC" (इसके बाद "विचाराधीन व्यापार चिह्न") के तहत वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और संबद्ध और संज्ञानात्मक वस्तुओं/उत्पादों में उपयोग करने, बेचने, बिक्री के लिए पेशकश करने, विज्ञापन देने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वाद से प्रदर्शित करने या किसी अन्य तरीके या तरीके से काम करने से रोकने के लिए एक डिक्री जारी की जाए।

3. अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी भी इलेक्ट्रोड के निर्माण और बिक्री में लगे हुए हैं। अपीलकर्ता दावा करता है कि वह विचाराधीन व्यापार चिह्न का स्वामी है और विचाराधीन व्यापार चिह्न के तहत सत्तर से अधिक देशों को वस्तुओं का निर्यात करता है। अपीलकर्ता ने अपने कारोबार का विवरण प्रस्तुत किया था, जो वर्ष 2004-2005 में ₹1,76,31,937/- से बढ़कर वर्ष 2016-2017 में ₹3,13,14,84,815/- हो गया था। अपीलकर्ता का दावा है कि उसने विचाराधीन व्यापार चिह्न के तहत बेचे जाने वाले अपने माल को लेकर बाजार में अपार लोकप्रियता हासिल की है।

4. प्रतिवादी अपने व्यापार चिह्न "SUPERON" के साथ अपनी पैकेजिंग पर विचाराधीन व्यापार चिह्न (VAC - PAC) का भी उपयोग कर रहा है।

5. जब पहली तिथि को वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तो उस पर सुनवाई हुई थी और आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। वाद में सम्मन जारी नहीं किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व 02.04.2018 को आयोजित सुनवाई में किया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वाद का विरोध किया और प्रस्तुतियाँ दीं, जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि वाणिज्यिक विवादों से जुड़े वादों पर लागू सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत, इस आधार पर वाद खारिज किया जा सकता है कि अपीलकर्ता के वाद में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के दावे की गुण-दोष के आधार पर जांच की थी और निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ता के उक्त वाद में सफल होने की कोई संभावना नहीं थी और तदनुसार उसे खारिज कर दिया था।

6. आरोपित आदेश को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि विचाराधीन व्यापार चिह्न, जिसका उपयोग प्रत्यर्थी द्वारा अपनी पैकेजिंग पर किया जा रहा था, अपीलकर्ता के लिए अद्वितीय था। विचाराधीन व्यापार चिह्न 'वैक्यूम पैकेजिंग/पैक' अभिव्यक्ति से लिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश

ने तर्क दिया कि सभी इलेक्ट्रोड वैक्यूम पैक थे और विचाराधीन व्यापार चिह्न केवल वर्णनात्मक था। इस प्रकार, अपीलकर्ता उक्त चिह्न के उपयोग के लिए किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं करेगा।

7. वर्तमान अपील में इस न्यायालय के विचारणीय प्रारंभिक प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने बिना समन जारी किए तथा अपीलकर्ता/वादी को यह सूचित किए बिना कि न्यायालय का इरादा सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के अंतर्गत सारांश निर्णय द्वारा वाद का निपटान करने का था, प्रथम सुनवाई में गुण-दोष के आधार पर वाद को खारिज करने में कोई गलती की थी।

8. इस संबंध में, सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

**“आदेश XIIIक  
सारांश निर्णय**

1. *वादों का दायरा और उनके श्रेणी जिन पर यह आदेश लागू होता है।* (1) यह आदेश उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा न्यायालय मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना किसी भी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित दावे का फैसला कर सकती हैं।

(2) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, "दावा" शब्द में शामिल होंगे:

(क) दावे का अंश;

(ख) कोई विशेष प्रश्न जिस पर दावा (चाहे वह पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से) निर्भर करता हो; या

(ग) एक प्रतिवाद, जैसा भी मामला हो।

(3) इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, इस आदेश के अंतर्गत सारांश निर्णय के लिए आवेदन किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में नहीं किया जाएगा, जो मूल रूप से आदेश XXXVII के अंतर्गत सारांश वाद के रूप में दायर किया गया हो।

*2. सारांश निर्णय के लिए आवेदन का चरण.- आवेदक प्रतिवादी को समन तामील होने के बाद किसी भी समय सारांश निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है:*

बशर्ते कि, न्यायालय द्वारा वाद के संबंध में मुद्दे तय कर दिए जाने के बाद ऐसे आवेदक द्वारा सारांश निर्णय के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

*3. संक्षिप्त निर्णय का आधार-* न्यायालय किसी दावे पर वादी या प्रतिवादी के खिलाफ संक्षिप्त निर्णय दे सकता है यदि वह मानता है कि -

(क) वादी के पास दावे में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी के पास दावे के बचाव की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, जैसा भी मामला हो; और

(ख) मौखिक साक्ष्य दर्ज करने से पहले दावे का निपटारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कोई अन्य ठोस कारण नहीं है।

*4. प्रक्रिया -* (1) न्यायालय में संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन में, किसी भी अन्य मामले के अलावा आवेदक प्रासंगिक

समझ सकता है, इसमें नीचे उल्लिखित उपखंड (क) से (छ) में निर्धारित मामले शामिल होंगे:-

(क) आवेदन में एक विवरण होना चाहिए कि यह इस आदेश के तहत किए गए संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन है;

(ख) आवेदन को सभी भौतिक तथ्यों का सटीक रूप से खुलासा करना चाहिए और कानून के बिंदु, यदि कोई हो, की पहचान करनी चाहिए;

(ग) यदि आवेदक किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो आवेदक को -

(i) इसके आवेदन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य को शामिल करें, और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रासंगिक सामग्री की पहचान करना जिस पर आवेदक निर्भर करता है;

(घ) आवेदन में कारण बताना होगा कि दावे पर सफलता पाने या दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना क्यों नहीं है, जैसा भी मामला हो;

(ङ) आवेदन में यह बताना होगा कि आवेदक किस राहत की मांग कर रहा है और इस तरह की राहत की मांग के लिए संक्षेप में आधार बताए जाने चाहिए।

(2) जहाँ संक्षिप्त निर्णय के लिए सुनवाई तय की जाती है, वहाँ प्रत्यर्थी को कम से कम तीस दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए:-

(क) सुनवाई के लिए नियत तिथि; और

(ख) वह दावा जिस पर ऐसी सुनवाई में न्यायालय द्वारा निर्णय लेने का प्रस्ताव है।

(3) प्रत्यर्थी, संक्षिप्त निर्णय या सुनवाई की सूचना (जो भी पहले हो) के आवेदन की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, किसी भी अन्य मामले के अलावा खंड (क) से (छ) में उल्लिखित मामलों को संबोधित करते हुए जवाब दाखिल कर सकता है जो प्रत्यर्थी प्रासंगिक समझ सकता है:-

(क) उत्तर ठीक-ठीक होना चाहिए -

(i) सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना;

(ii) कानून के मुद्दे, यदि कोई हो, की पहचान करना; और

(iii) वे कारण बताएँ कि आवेदक द्वारा मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

(ख) यदि प्रत्यर्थी अपने उत्तर में किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो प्रत्यर्थी को -

(i) अपने उत्तर में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य को शामिल करें; और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रासंगिक सामग्री की पहचान करें जिस पर प्रत्यर्थी भरोसा करता है।

(ग) उत्तर में यह कारण बताना होगा कि दावे पर सफल होने या दावे का बचाव करने की वास्तविक संभावनाएं क्यों हैं, जैसा भी मामला हो;

(घ) उत्तर में उन मुद्दों को संक्षिप्त रूप से बताना चाहिए जिन्हें परीक्षण के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

(ङ) उत्तर को इस बात की पहचान करनी चाहिए कि वाद में और कौन सा साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाया जाएगा जिसे संक्षिप्त निर्णय के चरण में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका; और

(च) उत्तर में यह बताना होगा कि साक्ष्य या अभिलेख पर सामग्री, यदि कोई हो, के आलोक में न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए।

5. *संक्षिप्त निर्णय की सुनवाई के लिए साक्ष्य* – (1) इस आदेश में कुछ भी होने के बावजूद, यदि संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन में प्रत्यर्थी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो प्रत्यर्थी –

(क) ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करे; और

(ख) सुनवाई की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले आवेदन के प्रत्येक अन्य पक्षकार को ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां प्रदान करेगा।

(2) इस आदेश में कुछ भी होने के बावजूद, यदि संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदक प्रतिवादी के दस्तावेजी साक्ष्य के जवाब में दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो आवेदक को:—

(क) प्रति उत्तर में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करें; और



(ख) सुनवाई की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले आवेदन के प्रत्येक अन्य पक्ष को ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां प्रदान करें

(3) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, उप-नियम (1) और (2) के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) दाखिल किया गया है यदि ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पहले ही दायर किया जा चुका है; या

(ख) उस पक्ष को दिया गया है जिस पर यह पहले से ही दिया जा चुका है।

6. आदेश जो न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं - (1) इस आदेश के तहत किए गए आवेदन पर, न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है कि वह निम्नलिखित सहित अपने विवेकाधिकार में उचित समझे:-

(क) दावे पर निर्णय;

(ख) यहाँ उल्लिखित नियम 7 के अनुसार सशर्त आदेश;

(ग) आवेदन को खारिज करना;

(घ) दावे के एक अंश को खारिज किया गया और दावे के एक अंश पर निर्णय जो खारिज नहीं किया गया है;

(ङ) अभिवचनों को (चाहे वह पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से) निरस्त करना; या

(च) आदेश XV-क के तहत मामले के प्रबंधन के लिए आगे बढ़ने के निर्देश।

(2) जहां न्यायालय उपनियम (1) (क) से (छ) में उल्लिखित आदेशों में से कोई भी आदेश देता है, वहां न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।

7. *सशर्त आदेश* - (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह संभव है कि दावा या बचाव सफल हो सकता है, लेकिन यह असंभाव्य है कि ऐसा होगा, न्यायालय नियम 6 (1) (ख) में निर्धारित सशर्त आदेश दे सकता है।

(2) जहाँ न्यायालय एक सशर्त आदेश देता है, वह कर सकता है:

(क) इसे निम्नलिखित सभी या किसी भी शर्त के अधीन बनाएँ:-

- (i) किसी पक्ष से न्यायालय में राशि जमा करने की अपेक्षा करना;
- (ii) दावे या बचाव के संबंध में, जैसा भी मामला हो, किसी पक्ष को निर्दिष्ट कदम उठाने के लिए बाध्य करना;
- (iii) किसी पक्षकार को, जैसा भी मामला हो, लागत की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी सुरक्षा देने या ज़मानत प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे न्यायालय उचित और उचित समझे;
- (iv) ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित करें, जिनमें वाद विचाराधीनता रहने के दौरान किसी भी पक्ष को होने वाले नुकसान की भरपाई के वाद प्रतिभूति प्रदान करना शामिल है, जैसा कि

न्यायालय अपने विवेकाधिकार में उचित  
समझे; और

(ख) सशर्त आदेश का पालन करने में विफलता के परिणामों को निर्दिष्ट करें, जिसमें उस पक्ष के खिलाफ निर्णय पारित करना शामिल है जिसने सशर्त आदेश का पालन नहीं किया है।

8. *लागत अधिरोपित करने की शक्ति* - न्यायालय संहिता की धारा 35 और 35क के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन में लागत के भुगतान के लिए आदेश दे सकता है।”

9. सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि न्यायालय मुद्दों को तैयार करने से पहले, प्रारंभिक चरण पर दावों पर आदेश या निर्णय पारित कर सकता है। सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के नियम 2 के अनुसार, आवेदक प्रतिवादी को सम्मन भेजे जाने के बाद किसी भी समय सारांश निर्णय के लिए आवेदन करने का हकदार है। सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के नियम 2 के अनुसार, आवेदक प्रतिवादी को सम्मन भेजे जाने के बाद किसी भी समय सारांश निर्णय के लिए आवेदन करने का हकदार है। यदि सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के नियम 2 के उप-नियम (क) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय दावों पर सारांश निर्णय दे सकता है यदि वह समझता है कि वादी के पास दावे पर सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी के पास वाद का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

यह इस शर्त पर है कि मौखिक साक्ष्य दर्ज करने से पहले दावे का निपटान क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं है।

10. सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के नियम 4 में पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सि.प्र.सं. के नियम 4 के उप-नियम (1) में स्पष्ट रूप से ऐसे मामले प्रदान किए गए हैं जिन्हें संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन में शामिल किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले, आवेदन में यह बताना होगा कि यह सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत संक्षिप्त निर्णय के लिए है। दूसरा, इसे सभी भौतिक तथ्यों का भी खुलासा करना चाहिए और कानून के बिंदु, यदि कोई हो, की पहचान करनी चाहिए। तीसरा, आवेदक किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करने का भी हकदार है, जिसे आवेदन में शामिल करने की आवश्यकता होती है और इसकी प्रासंगिक सामग्री की पहचान भी की जानी चाहिए। चौथा, आवेदक को स्पष्ट वाद से कारण बताना चाहिए कि वाद में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। और अंत में, आवेदक को मांगी गई राहत का उल्लेख करना चाहिए।

11. यदि संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन सि.प्र.सं. के आदेश 12 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसार किया जाता है, जैसा कि सि.प्र.सं. के आदेश 12 के नियम 2 में उल्लिखित है, तो न्यायालय को उक्त आवेदन की सुनवाई के लिए एक तिथि तय करने की आवश्यकता होती है। उक्त तिथि अनिवार्य रूप से तीस दिनों की अवधि के बाद होनी चाहिए क्योंकि सि.प्र.सं. के आदेश

XIIIक के नियम 4 के उप-नियम (2) में आदेश दिया गया है कि प्रत्यर्थी को सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि की कम से कम तीस (30) दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। न्यायालय को न केवल सुनवाई की तिथि का कम से कम तीस दिनों का नोटिस देना आवश्यक है, बल्कि उस दावे को भी देना आवश्यक है जो ऐसी सुनवाई में न्यायालय द्वारा तय किए जाने का प्रस्ताव है।

12. प्रत्यर्थी के पास संक्षिप्त निर्णय और सुनवाई की सूचना के लिए उक्त आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए तीस दिन हैं।

13. प्रत्यर्थी को उक्त आवेदन के जवाब में दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करने का भी अधिकार है जो उक्त जवाब के साथ होना चाहिए।

14. सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के नियम 5 के संदर्भ में, संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन में प्रत्यर्थी भी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करने का हकदार है। हालाँकि, प्रत्यर्थी को न केवल इस तरह के दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने की आवश्यकता होती है, बल्कि आवेदन में हर दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देने की आवश्यकता होती है। सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार, आवेदक को भी प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के जवाब में उस पर भरोसा करने का समान अवसर प्राप्त है।

15. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत अपनाई गई प्रक्रिया अनिवार्य है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतीक है, जिनका प्रतिकूल प्रणाली में न्यायिक कार्यवाही में पालन किया जाना आवश्यक है।

16. वर्तमान मामले में, यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा वाद में उठाए गए विवादों के निपटारे के लिए सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक से सहायता प्राप्त की है, लेकिन सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक में निर्धारित प्रक्रिया की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। सबसे पहले, उक्त वाद में कोई सम्मन जारी नहीं किया गया। सबसे पहले, उक्त वाद में कोई सम्मन देना जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के लिए संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन करने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था। दूसरा, भले ही उपरोक्त की अनदेखी की गई हो, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने वास्तव में सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आवेदन नहीं था जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया हो जिनके लिए अपीलार्थी का दावा अस्वीकार किए जाने योग्य था। इस तरह के किसी भी आवेदन के बिना, सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत एक संक्षिप्त निर्णय का सहारा शुरू अनुपस्थिति किया गया था। अपीलार्थी/वादी के पास प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए तर्कों का जवाब देने का कोई अवसर नहीं था।

17. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है और यदि सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत संक्षिप्त निर्णय दिया जाना है तो इसका पालन करना आवश्यक है।

18. **ब्राइट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम एम. जे. बिजक्राफ्ट एल.एल.पी. और अन्य: 2017 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 6394**, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

“22. सारांश निर्णय से संबंधित प्रावधान जो न्यायालयों को मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना वाणिज्यिक विवादों से संबंधित दावों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, प्रकृति में असाधारण हैं और सामान्य प्रक्रिया से अलग हैं जिसका एक सामान्य वाद में पालन किया जाता है। ऐसी स्थिति में, यह आवश्यक है कि शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए अन्यथा इसका परिणाम घोर अन्यायपूर्ण हो सकता है.....।”

19. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप वास्तव में अन्याय हुआ है क्योंकि इसने अपीलकर्ता/वादी को अपने वाद के विरोध में प्रस्तुत किए गए तर्कों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने से रोक दिया है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश को केवल इसी आधार पर अलग रखा जा सकता है।

21. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों के गुण-दोष के बारे में भी हमें संदेह है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश

ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि एक व्यापार चिह्न जो एक अंग्रेजी अभिव्यक्ति से लिया गया है, निहित रूप से वही अर्थ रखता है और इसलिए, एक स्रोत पहचानकर्ता के रूप में कार्य करने में असमर्थ है। यह बात सर्वविदित है कि आम उपयोग के कुछ शब्द भी द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर सकते हैं और वे मालिक के माल की पहचान करने वाले स्रोत के रूप में काम आ सकते हैं। उपरोक्त बातें कहने के बाद, हम इस संबंध में कोई और टिप्पणी करने से बचते हैं क्योंकि विवादों को पहले विचारण न्यायालय द्वारा ही संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारे इस निष्कर्ष को देखते हुए कि सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और योग्यता के आधार पर अपीलार्थी के दावों को संबोधित करना आवश्यक नहीं है।

22. विवादित आदेश को तदनुसार अलग कर दिया जाता है। वाद [सि.वा. (वाणि.) सं. 750/2018 शीर्षक *सुपरॉन श्वाइसटेक्निक इंडिया लिमिटेड बनाम मोदी हाइटेक इंडिया लिमिटेड*] को 02.04.2018 पर प्राप्त स्थिति में बहाल कर दिया गया है। विचारण न्यायालय विवादित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित विवादों पर विचार नहीं करेगा।

23. लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।



न्या. विभू बाखरू

न्या. तारा वितस्ता गंजू

फरवरी 06, 2024

‘जीएसआर’

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।